बाल कल्याण संगठनों के खिलाफ शिकायतें

597. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल कल्याण संगठनों में श्रमिकों की भर्ती तथा बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला तथा बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बाघव राजेश्वरी) : (क) से (ग) बाल कल्याण संगठन, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रमों का, बच्चों के लिए शिशुगृहों का संचालन कर रहे हैं तथा समेकित बाल विकास सेवाओं (आई. सी. डी. एस.) के अन्तर्गत कुछ परियोजनाओं का वित्तपोषण इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ये केन्द्र अवैतनिक स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जाते हैं। श्रमिकों की कोई भर्ती नहीं की जाती। वर्ष 1992-93 के दौरान इन केन्द्रों में बच्चों को दी जाने वाली खाद्य-सामग्री की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान में खेलकूद तथा शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ शिकायत

598. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितनी खेलकूद और शैक्षणिक संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक संस्था को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है;

(ख) कितनी संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें की गई हैं तथा इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है और ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जिन्हें भंग कर दिया गया है अथवा जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मुकुल वासनिक) (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार तथा राजस्थान में स्थित संस्थाओं को खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिये) इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण

ने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता छात्रों को 1986–87 से 1992–93 तक निम्नलिखित स्कूलों में दाखिल करने पर खर्च किया है :–

स्कूल का नाम	किया गया खर्च	प्रयोजन
1. बनस्थली विद्यापीठ स्कूल, बनस्थली।	6.45 लाख रु०	भोजन, आवास, ट्यूशन, शुल्क, खेल किट, पुस्तकें, स्टेशनरी,
2. भुपाल नोबल्स उच्चतर माध्यमिक स्कूल, उदयपुर।	7.37 लाख रु०	स्कूल की वर्दी, दाखिला शुल्क, परीक्षा शुल्क, चिकित्सा व्यय तथा एन. एस. टी. सी. छात्रों को बीमा के खर्च को पूरा करने के लिए।
3. श्री गुरू नानक खालसा उच्चतर माध्यमिक स्कूल, गंगानगर।	7.43 लाख रु०	

इसके अलावा प्रत्येक स्कूल को बुनियादी सुविधाओं के लिए एक बार 5.00 लाख रुपये तथा अनुरक्षण के लिए प्रति वर्ष 56,000/– का अनुदान दिया जाता है। शैक्षिक संस्थाओं के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर जिले की एक पंचायत के बारे में केन्द्रीय सहायता के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) राज्य सरकार ने संस्थाओं से वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।

विवरण

राजस्थान में खेलों की बुनियादी सुविधायें सृजित करने के लिये खेल और शैक्षिक संस्थाओं को दिया गया अनुदान

1989–90

क्र०सं०	संस्था का नाम	धनराशि
		रुपये
1.	खेल निदेशक, राजस्थान	37,50,000
2.	नगर पालिका बोर्ड, प्रतापगढ़	1,00,000
3	जीयलाल शिक्षण कालेज संस्थान, अजमेर	500

क्र०सं०	संस्था का नाम	धनराशि
4.	श्री एम.एल.पी. राजकीय कालेज, भीलवाड़ा	25,000
5.	बिड़ला तकनीकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी	2,92,500
	1990–91	
6.	प्रशासक, नगर पालिका बोर्ड मकराना	2,48,500
7.	महासचिव, जिला क्लब, पाली	35,000
8.	जिला टैनिस संघ, डूंगरपुर	5,440
9.	राजकीय कालेज, दौसा	66,000
10.	राजस्थान विश्वविद्यालय	2,00,000
11.	श्री जैन पी.जी. कालेज, नौखा	1,25,000
	1991–92	
12.	सचिव, युवा कार्य और खेल, जयपुर	90,00,000
13.	मुख्य अध्यापक राजकीय उ०मा० स्कूल, मालपुर	25,000
14.	राजस्थान राज्य खेल परिषद, जयपुर	29,00,000
15.	राजकीय व०उ०मा० स्कूल, जिला उदयपुर	6,719
16.	जोधपुर विश्वविद्यालय	70,000
17.	राजस्थान विश्वविद्यालय	2,00,000

Seminar on Child Power

599. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a two day seminar on Child Power was organised jointly by NCERT and the Child Trust of London in New Delhi recently;

(b) if so, what were the main observations and suggestions made therein for providing the child with opportunity to develop to its best self; and

(c) what decision and actions have been taken on the light thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Child-to-Child Programme is essentially an activity based approach to education, particularly health education which taps the 'Child Power' to disseminate important messages to the peer groups as well as the community at large.